Norms for working out tariff for SEBs

1122. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether some of the State Electricity Boards like the Rajasthan State Electricity Board have asserted that the norms for working out the tariff for the sale of energy by the National Thermal Power Corporation are clearly weighed against them; and

(b) if so, what is Government's reaction to such a resentment by the State Electricity Boards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) The difference of opinion between the National Thermal Power Corporation (NTPC) and the State Electricity Boards (including Rajasthan State Electricity Board) relaing to principles and normative parameters for working out tariff for sale of power from generating stations of NTPC had resulted in non-revision of tariff over a period of time. After numerous consultations with the State Electricity Boards Government of India decided to introduce with effect from 1st April, 1991, a station-wise two-part tariff for sale of power to the States in the interests of merit order operations and marginal price based on marginal cost of generation taking into account the recommendations of the K. P. Rao Committee (June, 1990) which was set up to formulate the principles and normative tariff for sale of power from Central Power Generating Stations.

संजय गांधी वोरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन

1123. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान संजय गांधी वोरसिंह पुर ताप विद्युत परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) इस परियोजना के समय पर पूरा नहीं हो पाने के क्या कारण थे और क्या उन अवरोधों को दूर कर दिया गया है; और

(ग) यहां पर उत्पादन कब तक प्रारंभ हो जाएगा और इस ताप विद्युत केन्द्र से कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होगा?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) संजय गांधी बीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना (2× 210 मे.वा.) चरण-1 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 723 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय में से अब तक परियोजना पर लगभग 390 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसमें चालू वर्ष (1991-92) के दौरान 102.44 करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के सन्दर्भ में खर्च किए गए 81 करोड़ रुपये शामिल हैं। यूनिट-1 से सम्बन्धित 70% बायलर उत्थापन एवं 42% टर्बाइन उत्थापन कार्य और यूनिट-2 से सम्बन्धित 50% बॉयलर उत्थापन एवं 10% टर्बाइन उत्थापन कार्य पूरे हो गये हैं। 1990-91 के दौरान यूनिट-1 के सम्बंध में बायलर हाइड्रोलिक परीक्षण एवं टर्बो जनरेटर उत्थापन कार्य तथा यूनिट 1 एवं 2 के सम्बन्ध में संधारित्र उत्थापन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान बायलर प्रदीपन सम्बन्धी कार्य किए जाने का कार्यक्रम है।

परियोजना के चरण-1 के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारणों में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के पास उपस्कर की सप्लाई हेतु भुगतान किए जाने के लिए निधियों की कमी होना है। जिसके परिणामस्वरूप उपस्कर सप्लाईकर्ताओं द्वारा बायलर एवं टर्बाइन सामग्री की सप्लाई में विलम्ब हुआ है। उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन